

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.- 2025/21

उनवान

मोहनलाल पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
राज०

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा


(रेस्पोजेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पोजेण्ट की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 11.11.2024 मि०नं० 253/2024
न्यायालय तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : ..19/9/26..

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा के द्वारा ग्राम डडवाडा पटवार नोनेरा द्वारा ख.न. 230,144,145,146,147,148,177,211,212,213,214,218,227,228,229, कुल किता 12 रकबा 12.98 है. भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को 3 माह का सिविल कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। इस कारण अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सजा से दण्डित किये जाने में कानूनी त्रुटि की है क्योंकि अपीलान्ट को न तो जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है जो कि त्रुटिपूर्ण है।
3. उक्त आराजी में अपीलान्ट मूल खातेदार मोहनलाल पुत्र प्रहलाद के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा सिलिंग एक्ट के तहत उक्त भूमि दिनांक 5.5.1972 को अधिग्रहित कर ली गई। इसके पश्चात दिनांक 22.01.1991 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार उक्त आराजी को पुनः मूल खातेदार को संभलाये जाने का आदेश प्रदान किया गया जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 76 दिनांक 4.07.1991 के अनुसार उक्त भूमि पुनः दर्ज की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की लापरवाही के कारण उक्त भूमि जमाबंदी में अमल दरामद नहीं हो सकी। उसके पश्चात पुनः मूल खातेदार मदन मोहन के खिलाफ धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई जिसका निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहा से दिनांक 20.03.1999 के आधार पर उक्त भूमि को पुनः इन्तकाल संख्या 76 के

अति.  जिला कलेक्टर
कोटा



अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये लेकिन उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खातेदार के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही निरन्तर रखी। उसके पश्चात सम्वत 2080 में अपीलान्ट के विरुद्ध हलका पटवारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही की गई जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य जाने योग्य है।

4. अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी दिनांक 5.2.2025 को अपीलान्ट पुत्र प्रेमचन्द तहसील कार्यालय में स्टे की नकल लेने के लिया तब जानकारी हुई। अतः अपील में डिले हुए समय को कन्डोन किया जाकर उक्त अपील को अवधि मध्य माना जावे।
अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.11.2024 को रिस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट कह सजा पर रोक लगाई जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान कि जावे।
4. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोजेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम डडवाडा पटवार नोनेरा द्वारा ख.न. 230,144,145,146,147,148,177,211,212,213,214,218,227,228,229, कुल किता 12 रकबा 12.98 है। भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को 3 माह का सिविल कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। उक्त आराजी में अपीलान्ट मूल खातेदार मोहनलाल पुत्र प्रहलाद के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा सिलिंग एक्ट के तहत उक्त भूमि दिनांक 5.5.1972 को अधिग्रहित कर ली गई। इसके पश्चात दिनांक 22.01.1991 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार उक्त आराजी को पुनः मूल खातेदार को संभलाये जाने का आदेश प्रदान किया गया जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 76 दिनांक 4.07.1991 के अनुसार उक्त भूमि पुनः दर्ज की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की लापरवाही के कारण उक्त भूमि जमाबंदी में अमल दरामद नहीं हो सकी। उसके पश्चात पुनः मूल खातेदार मदन मोहन के खिलाफ धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई जिसका निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहा से दिनांक 20.03.1999 के आधार पर उक्त भूमि को पुनः इन्तकाल संख्या 76 के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये लेकिन उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खातेदार के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही निरन्तर रखी। उसके पश्चात सम्वत 2080 में अपीलान्ट के विरुद्ध हलका पटवारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही की गई जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य जाने योग्य है।

5. रेस्पोजेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अपीलांट का विधि विरुद्ध कब्जा किया हुआ है। तथा अपीलांट को पूर्व उक्त आराजी पर बेदखल किया गया था। अतः अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है। अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर सिलिंग कार्यवाही होना व न्यायालय के आदेश से पुनः सिलिंग कार्यवाही समाप्त की जाकर विवादग्रस्त आराजी पुनः खाते दर्ज होना अपनी बहस व अपील मेमो मे जाहिर किया है। वकील अपीलांट द्वारा यह भी जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिलिंग कार्यवाहीयो के दौरान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय जमाबंदी मे अमल दरामद नहीं कर अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त



अति. जिला कलक्टर
कोटा

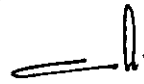
आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त को 50 गुना शास्ति व 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार न्यायालय का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्त को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विवादित आराजीयात् के संबध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर गौर करते हुए निर्णय अपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पीपल्दा के निर्णय दिनांक 11.11.2024 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व दस्तावेज की जाँच एवं सुनवाई का अवसर देते पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 19/11/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
मुद्रा




(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा